

संपादकीय

उच्च शिक्षा का अस्तित्व

पार्श्वम बंगाल में उच्च शिक्षा अस्तित्व सकट में है। एक स्तर पर, यह पूरे भारत में विश्वविद्यालय प्रणाली के लिए सच है, जो केंद्र सरकार की वर्तमान नीति के तहत उजागर हो रही है। लेकिन बंगाल गुमराह नीति से धीरे-धीरे उबरने से संतुष्ट नहीं है। राज्य-स्तरीय शासकों के सक्रिय कुशासन के कारण इसके विश्वविद्यालय चरमरा रहे हैं। मुझे एक राष्ट्रीय अखबार में यह लिखने में कोई खुशी नहीं है, लेकिन संकट को पहचानने की जरूरत है। यह और भी अधिक निंदनीय है, क्योंकि चाटुकारिता की निष्क्रिय संशयवादिता को धता बताते हुए, बंगाल के राज्य-संचालित विश्वविद्यालय भारत में सर्वश्रेष्ठ में से एक हैं। जादवपुर विश्वविद्यालय केंद्र सरकार के राष्ट्रीय संस्थागत रैकिंग फ्रेमवर्क में सार्वजनिक और निजी, पहले पांच या छह भारतीय विश्वविद्यालयों में और राज्य संचालित परिसरों में पहले स्थान पर है। कलकत्ता विश्वविद्यालय कभी पीछे तो कभी आगे होता है। (एकमात्र प्रतियोगी तमिलनाडु का अन्ना विश्वविद्यालय है) इन संस्थानों में कई समस्याएँ हैं, लेकिन हम लगातार उनके वास्तविक गुणों को नजरअंदाज करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में परिदृश्य बाधित हुआ है य परिणाम अब हमारे चेहरे पर सामने आ रहे हैं। मूल कारण राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच का झगड़ा है, जिससे विपक्ष शासित कई राज्य प्रभावित हैं। बंगाल में मुख्य युद्धक्षेत्र शिक्षा है। राज्यपाल सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं। हाल के कुलपतियों ने विश्वविद्यालय मामलों पर सीधे नियंत्रण के लिए अपनी पूर्व औपचारिक भूमिका को त्याग दिया है। बदले में, राज्य सरकार ने अपनी पकड़ कड़ी कर दी है। शैक्षणिक स्वायत्तता खत्म हो गई है द एक परिणाम जिसे दोनों सत्ताओं खेमों है। वह जहां भी जाते हैं भीड़ खींचते नजर आते हैं। अक्सर, वह उनके साथ बैठते हैं, और उनके चारों ओर प्रतिनिधि मंडली में आमतौर पर युवा पुरुष और महिलाएं शामिल होती हैं, विशेष रूप से जींस में युवा महिलाएं—स्वतंत्र-उत्साही उदारगादी जो राहुल गांधी की कॉमरेड उपस्थिति में आश्वासन पाते हैं। वे 'हम होंगे कामयाद' की भावना पर आधारित गीत गाते हैं। फिर वे टूट जाते हैं और राहुल गांधी दूसरी जगह चले जाते हैं। थोड़े बदलाव के साथ दृश्य दोहराया जाता है। क्या इन गायकों और ऐसी ही 'सूफी' आत्माओं का वास्तविक राजनीति के संदर्भ में कोई मतलब है? इन सभाओं की प्रकृति शायद कॉलेज चुनाव के लिए अधिक उपयुक्त है। पिछले साल यात्रा के पहले चरण में, कोई भी इस अभियान को कुछ आशा के साथ देख सकता था। लेकिन इसके बाद हुए विधानसभा

प्राचीनता दर्शाते हैं। किंतु एक समाजान्तरिका पाता उत्तरार्थक विषयों ने सराहा है। दोनों चाहेंगे कि एक आज्ञाकारी संकाय उनकी बोली को पूरा करे। कुलपतियों की नियुक्ति पर संकट की घड़ी आ गई है। अब एक और सबप्लॉट सामने आ रहा है। कुछ साल पहले ऐसी नियुक्तियों में कुछ अनियमितताएं पकड़ी गई थीं। क्षति की भरपाई करने के बजाय, राज्य सरकार ने कानून में संशोधन करने की मांग की, ताकि वास्तव में, अनियमितताएं बनी रहें। जैसा कि अनुमान था, चांसलर ने अपनी ही चप्पू चला दी। म्यूजिकल चेयर का धिनौना खेल शुरू हुआ, प्रत्येक पक्ष ने अपने—अपने प्रत्याशियों को नियुक्त किया और दूसरे को कमज़ोर कर दिया। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जिसने एक कमेटी का गठन किया है। इस बीच, यथार्थिति जारी है, जिसका प्रभावी रूप से मतलब है कि कुलाधिपति द्वारा नामित कुलपतियों का एक समूह उन सीटों को सुशोभित करना जारी रखेगा, जिन पर वे किसी विशेष क्षण में संयोग से बैठे थे। यथार्थिति बनाए रखने के लिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जा सकता। कौन से निर्णय महत्वपूर्ण हैं? और महत्वपूर्ण निर्णय लिए बिना कोई विश्वविद्यालय कैसे चला सकता है? बड़े और छोटे प्रशासनिक निर्णय विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा लिए जाते हैं। अस्थायी कुलपति परिषद की बैठकें नहीं बुला सकते। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल एक—दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन दोनों फुटबॉल खेलते हैं। इसी प्रकार, हमारे झगड़ालू शासक भी बंगाल में उच्च शिक्षा को पंगु बनाने के सामान्य मुद्दे पर एकजुट हैं। दीक्षांत समारोह आयोजित करने को लेकर मामला तूल पकड़ गया। दो विश्वविद्यालयों ने कुलाधिपति की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जबकि राज्य सरकार ने विरोध किया। फिर भी जब जादवपुर ने बिल्कुल उन्हीं परिस्थितियों में अपने दीक्षांत समारोह की घोषणा की, तो चांसलर इतने नाराज हो गए कि उन्होंने कूलपति (अपने स्वयं के नामांकित व्यक्ति) को पूरी

जानकारी के साथ बर्खास्त कर दिया कि वह किसी अन्य को नियुक्त नहीं कर सकते। राज्य सरकार ने अपने पहले के रुख से पलटते हुए अब दीक्षांत समारोह आयोजित करने का समर्थन किया और कुलपति को बहाल करने का प्रयास किया। दोनों पक्षों की भूमिकाओं में यह उलटफेर दिखाता है कि कैसे वे शुद्ध विरोध के कारण आगे बढ़ रहे हैं, जिससे विश्वविद्यालय को भी अतिरिक्त क्षति हो रही है। दीक्षांत समारोह तो हो गया, लेकिन उसके बाद कुलपति ने पद छोड़ दिया। अब पूर्णतया प्रबंधन शून्य हो गया है। यहां तक कि नियमित प्रशासन को भी कुलपति और कार्यकारी परिषद से निरंतर अनुमोदन और निर्देशों की आवश्यकता होती है। दोनों ने काम करना बंद कर दिया है। कुलपति के बीमार पड़ने जैसी 'सामान्य' आपात स्थितियों के लिए प्रावधान हैय वर्तमान जैसी विचित्र स्थिति के लिए कोई नहीं। चौतरफा नुकसान से तीन महत्वपूर्ण मुद्दे उभरकर सामने आते हैं। पहला केंद्रीय अनुदान से संबंधित है। इन्हें अलग-अलग 'शून्य-शेष' खातों में रखा जाता हैय खर्च न की गई धनराशि एक समय सीमा के बाद दिल्ली वापस आ जाती है। वर्तमान गतिरोध में, विभाग (विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के) 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले उपकरण और बुनियादी ढांचे के लिए अपनी मेहनत से अर्जित अनुदान का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस वर्ष के धन को खर्च करने में विफलता अगले वर्ष के आवंटन के लिए विनाशकारी होगी। क्या विभाग इस शारीरिक आघात से बच सकते हैं? दूसरा मुद्दा कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित है। भारत भर के अधिकांश सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की तरह, कई विभाग आधी क्षमता पर चल रहे हैं। सरकार अब नियुक्तियों में पहले की तुलना में बड़ी भूमिका निभाती है, या निभाने में विफल रहती है। चांसलर भी एक प्रतिनिधि नामित करते हैं। इस बीच छात्रों की कमी हो गई है, और युवा विद्वान नौकरियों की कमी से जुझ रहे हैं।

यूसीसी पर



ललित
उत्तराखण्ड मंत्रिमंडल ने समान साचार संहिता (यूसीसी) के द्वापट बैल को मंजूरी दे दी है, इसी चार देनों के विशेष सत्र में इसे आसानी से पारित भी कर दिया जायेगा। इस तरह देश को आजादी मिलने के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखण्ड पहला राज्य बन जाएगा। इससे पहले गोवा में यह लागू है। की स्थापना के लिये इससे अपूर्व वातावरण निर्मित होगा। यह उत्तराखण्ड ही नहीं, समूचे भारत की बड़ी जरूरत है। समानता एक सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक लोकतांत्रिक मूल्य है। इस मूल्य की प्रतिष्ठापना के लिये समान कानून की अपेक्षा है। यूसीसी देश की राजनीति के सबसे विवादित मुद्दों में रहा है। हालांकि संविधान में

राष्ट्र की चेतना जागरण का स्वजन पूरा नहीं हो सकता। उत्तराखण्ड एवं गोवा के बाद असम और गुजरात जैसे राज्य भी समान आचार संहिता को लागू करने की तैयारी में हैं। भारतीय जनता पार्टी एवं नरेन्द्र मोदी सरकार यूसीसी लागू करने की मांग जोरदार तरीके से करती आ रही है और इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाया है। भारतीय न्यायपालिका की तरफ से भी बार-बार इसे लागू

कांग्रेस बनाम सहयोगी दलों से बाहर निकलने का रास्ता

आदित्य

जब यह कालम लिखा जा रहा
राहुल गांधी की भारत जोड़े
या यात्रा झारखंड से गुजर रही
वह जहां भी जाते हैं भीड़ खीचते
र आते हैं। अक्सर, वह उनके
पास बैठते हैं, और उनके चारों
प्रतिनिधि मंडली में आमतौर
युवा पुरुष और महिलाएं शामिल
हैं, विशेष रूप से जींस में
महिलाएं—स्वतंत्र-उत्साही
रवादी जो राहुल गांधी की
रेड उपस्थिति में आश्वासन पाते
थे 'हम होंगे कामयाब' की भावना
आधारित गीत गाते हैं। फिर वे
जाते हैं और राहुल गांधी दूसरी
ह चले जाते हैं। थोड़े बदलाव
साथ दृश्य दोहराया जाता है।
इन गायकों और ऐसी ही 'सूफी'
माओं का वास्तविक राजनीति
संदर्भ में कोई मतलब है? इन
ओं की प्रकृति शायद कॉलेज
व के लिए अधिक उपयुक्त है।
ले साल यात्रा के पहले चरण
कोई भी इस अभियान को कुछ
को के साथ देख सकता था।
न इसके बाद हुए विधानसभा

चुनाव में तेलंगाना को छोड़कर बाकी जगहों पर नतीजे कांग्रेस के लिए सुखद नहीं रहे। हालांकि कुछ सहानुभूति रखने वाले मीडिया के लोग यह सिद्धांत पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जिन यात्रा क्षेत्रों को कवर किया, उससे कांग्रेस को मतदाता मिले, लेकिन यात्रा और वोटों के बीच वास्तविक सह-संबंध का कोई वास्तविक सांख्यिकीय प्रमाण नहीं है। किसी भी स्थिति में, विधानसभा परिणामों को देखते हुए, इसका कोई वास्तविक परिणाम नहीं हो सकता है। जैसे-जैसे आम चुनाव नजदीक आ रहा है, न्याय यात्रा लगातार प्रतिकूल होती दिख रही है। उदाहरण के लिए, बिहार में, जब यात्रा आनंदमय हो रही थी, नीतीश कुमार, जो उस वास्तविक गटर का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हृदय प्रदेश की राजनीति है, ने इसे भारत गुट से अलग होने, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा देने और शपथ लेने का एक उपयुक्त अवसर पाया। फिर से भाजपा के समर्थन से – तीन दिनों के अंतराल

क्षेत्र खाली करना होगा ताकि वे वहां से चुनाव लड़ सकें। मुद्दा यह है कि क्षेत्रीय राजनीति एक अत्यधिक तरल मैट्रिक्स है। नई यात्रा के साथ समस्या सिर्फ वह नहीं है जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं राहुल को पार्टी मुख्यालय में रहना चाहिए, मैदान से बाहर नहीं, ताकि राजनीतिक समीकरण बनाए जा सकें, संगठनात्मक निर्णय लिए जा सकें और रणनीतियां तैयार की जा सकें। इसका कोई खास मतलब नहीं है क्योंकि राहुल गांधी ने पार्टी के अध्यक्ष चुनाव के समय ही स्पष्ट कर दिया था कि इन पहलुओं का ध्यान पार्टी अध्यक्ष मलिलकार्जुन खड़गे रखेंगे और वह मैदान में रहेंगे। यह कोई बुरी रणनीति नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता है कि राहुल गांधी को अपनी सीमाओं का एहसास है। माना कि वह बंद करने में बातचीत करने में अच्छे नहीं हैं। लेकिन समस्या यह है कि वह अपने क्षेत्र के काम को बोटों में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ एक कारण से, क्षेत्रीय दलों – जिनमें से कुछ

भारतीय गुट के सहयोगी हैं दूसी की अस्तित्व की प्राथमिकताएं कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ टकराव की स्थिति में हैं। बाद वाले का जीवन पहले की मृत्यु है। जब भी विपक्ष एक साथ आता है, तो इससे कांग्रेस को फायदा होता है और क्षेत्रीय दलों की पहचान लगभग खत्म हो जाती है। नरेंद्र मोदी को हारते देखने के लिए वे खुद को क्यों नष्ट करेंगे? कोई भी आसानी से कह सकता है कि मोदी ही हैं जिनकी वजह से, उदाहरण के लिए, ममता जीवित हैं और सक्रिय हैं। दरअसल, मोदी को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय ताकत के रूप में जीवित रखना क्षेत्रीय नेताओं के हित में है। वे मोदी के विरोध में अपनी पहचान और प्रासंगिकता को परिभाषित करते हैं। अब जब राहुल गांधी यात्रा के लिए प्रतिबद्ध हैं तो उनके पास इसे पूरा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वह मार्च के तीसरे सप्ताह में किसी समय दिल्ली वापस आएंगे। दिल्ली वापस आकर, एक चीज जो वह करना चाहेगा वह है प्यार के बारे में बात करना बंद कर देना।

पारतीय राजनीति सूफी भूमि नहीं है, जैसा कि मोदी भी अच्छी तरह जानते हैं। यही कारण है कि वह कियावेलियन सिद्धांत में विश्वास लगाना चुनते हैं कि एक नेता को जनता में बने रहने के लिए प्यार के जाय डर को प्रेरित करना चाहिए। अहुल गांधी वास्तव में क्या कर सकते हैं दृढ़ चूंकि उनके और उनकी पार्टी के पास देने के लिए कोई वास्तविक कल्पिक आर्थिक दृष्टि नहीं है, केवल आभकामनाएं हैं — वह एक ऐसा गम करना है जो बूथों पर चुनाव रिणामों को बदल सकता है। यह चुनाव के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा ईवीएम मॉडल का मुकाबला लगाने के लिए है। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में एक मौखिक घटेघणी की थी कि मतदाता—सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल रिकार्ड के खिलाफ ईवीएम डेटा बिनी क्रॉस-चेकिंग के पैमाने को बढ़ाने में चुनाव आयोग का काम बिना कैसी 'बड़े लाभ' के बढ़ जाएगा, अत्यं यह है कि स्रोत कोड का अशीन की देखरेख स्वयं एक समिति गारा की जाती है।

परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा

आदित्य

अगस्त 2021 में काठिन दोर के जब जो बिडेन ने इंडो-पौसिफिक अपना ध्यान केंद्रित करने और के उदय का मुकाबला करने के अमेरिका को अफगानिस्तान से निकालने पर जोर दिया, तो युद्ध के युग के अंत के रूप में इदिया। इस बात का जरा भी वास नहीं था कि कुछ महीनों के भड़की दो आग दुनिया को खोय थिएटर और मध्य पूर्व में खींच लेंगी। 24 फरवरी, 2022 नब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो यह गड़बड थाय काला सागर क्षेत्र ई हिस्सेदारी वाले बहुत सारे गाड़ी थे, लेकिन इसमें सीधे तौर अमेरिका की कोई भागीदारी नहीं नाटो और अमेरिका ने यूक्रेन के म से युद्ध लड़ा, जिससे कई से युद्ध समग्री की आपूर्ति लाए बनीं। तब से यह एक

कलासिक गतिरोध में बदल गया है, हालांकि क्षमता पर धारणाएं बहस योग्य हैं। इजराइल—हमास युद्ध, जो मूल रूप से फिलिस्तीनी मुद्दे से ध्यान भटकने से रोकने के लिए हमास द्वारा डिजाइन किया गया एक असमर्पित युद्ध है, अब मध्य पूर्वी क्षेत्र में फैल रहा है, जिससे एक ऐसी गड़बड़ी पैदा हो रही है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है। जबकि इजरायल और हमास के बीच मुख्य युद्ध इजरायलियों द्वारा जान—माल के भारी नुकसान के बावजूद गतिरोध पर पहुंच गया है, यह साइड—शो है जो अधिक चिंता का कारण बन रहा है। मुख्य युद्ध अन्य घटनाओं को व्यापक रूप से प्रभावित करने की अपनी क्षमता से अलग है, हालांकि यह इन सभी घटनाओं को शुरू करने के लिए जिम्मेदार था। पहला लेबनान में हिजबुल्लाह है, जिसने अपनी उत्तरी सीमा पर इजराइल पर दबाव डाला है और अगर वह चाहे तो तनाव बढ़ाने के लिए इजराइल के भीतर कई मिसाइल हमले शुरू करने की क्षमता रखता है। इसकी प्रासांगिकता उत्तर में इसकी खतरनाक उपस्थिति और ईरान से छद्म खतरे के रूप में अस्तित्व में है और इससे अधिक निर्णायक कुछ भी नहीं है। फिर हाँथिस हैं। उन्हें लंबे समय से ईरान द्वारा यमन में प्रॉक्सी के रूप में न केवल अपना प्रभाव फैलाने के लिए प्रायोजित किया गया है, बल्कि लाल सागर के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं और तेल व्यापार की सुविधा प्रदान करने वाले प्रमुख समुद्री मार्गों से यमन की निकटता के कारण भू—रणनीतिक ऊपरी हाथ बनाए रखने के लिए भी प्रायोजित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय गतिरोधों में यह एक महत्वपूर्ण क्षमता है, जहां कई देशों की आर्थिक भलाई दांव पर होगी। यह बदले में बदले की क्षमता भी है, जहां ईरान के विरोधि

यों द्वारा फारस की खाड़ी को बंद करने की संभावित संभावना का मुकाबला लाल सागर कार्ड से किया जा सकता है लेवांत में सत्ता बरकरार रखने और मध्य पूर्व में पर्षिंगमी प्रभाव को रोकने की ईरान की मंशा भंगुरता की रणनीति की ओर ले जाती है। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है, जब ईरान ने कथित तौर पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस (आईआरजीसी) द्वारा समर्थित प्रॉक्सी द्वारा सीमित हमलों के माध्यम से अपनी क्षमता का संदेश देने का विकल्प चुना है। जनवरी 2020 में बगादाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक लक्षित ड्रोन हमले द्वारा आईआरजीसी के प्रसिद्ध कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या इस तरह के गतिरोधों में से पहली नहीं थी। हालांकि, ईरान ने सक्रिय रूप से एक सीमा पार करने से परहेज किया है लेकिन जब इसके नेताओं को निशाना बनाया जाता

सुनक को अपनी छवि बेहतर बनाने में मदद

आसिप

ओर इसलिए, हम जानते हैं में – लोग आश्चर्यचकित रह जब यह पता चला कि प्रधान नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम के उद्घाटन से पहले करीब ह दिनों तक उपवास किया था। ने पास केवल नारियल पानी था और जब उन्होंने देश चलाना और करना जारी रखा तो उन्होंने धृष्टिक धैर्य दिखाया। इस प्रकार भास्म-नियन्त्रण एक ऐसी चीज़ है के बारे में हम यह सुनने के हैं कि वह कहाँ चित्तित है दृ इसलिए क्या अन्य विश्व नेता ट” ट्रैक पर बहुत पीछे रह सकते इस प्रकार, हाल ही में प्रधान ऋषि सुनक ने यह कहकर को प्रभावित किया है कि वह मेत रूप से रविवार की शाम से होकर मंगलवार की सुबह तक स घंटे का उपवास करते हैं।

या कॉफी ही पीते हैं। यूके में, इस प्रकार के उपवास के लाभकारी प्रभाव कैसे हो सकते हैं, इस पर चर्चा करना सभी के लिए एक बहुत ही सुखद मनोरंजन था। मीडिया में गरमागरम चर्चाएं हुई हैं और प्रमुख आहार विशेषज्ञों से सलाह मिली है कि यह आपके चयापचय पर क्या प्रभाव डाल सकता है। बेशक, 5:2 “फास्ट डाइट” पिछले कुछ वर्षों से पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गई है, और “इंटरमिटेंट फास्टिंग” एक चर्चा का शब्द है लेकिन ये सभी वजन घटाने के तरीकों के रूप में हैं। श्री मोदी ने जो किया वह आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए भी था और हम जानते हैं कि वह हर साल नवरात्र के दौरान उपवास भी करते हैं। हम श्री सुनक के उपवास की प्रेरणा नहीं जानते दृ लेकिन यह निश्चित रूप से उनके अभ्यस्त उपवास को प्रकट करने और कहानी को बदलने की

है जिसे एक मजबूत “कठोर ऊपरी हॉट” ने हल न किया हो। लेकिन हालिया खबर यह है कि सारा फर्ग्युसन, डचेस ऑफ यॉर्क दृ जिनकी शादी प्रिंस एंड्रयू से हुई थी दृ को मेलेनोमा, यानी त्वचा कैंसर का पता चला है। केट के विपरीत, जिसकी रहस्यमय सर्जरी के बारे में हम अभी भी नहीं जानते हैं सारा अपने स्वयं के निदान, पुनर्ग्राह्ति और उपचार के साथ सार्वजनिक हो गई है। इससे अपने स्वयं के संदिग्ध मेलेनोमा के लिए चेकअप के लिए जाने वाले लोगों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है दृ और एनएचएस की रिपोर्ट है कि मेलेनोमा के लिए अस्पताल का दौरा अब पिछले हफ्तों की तुलना में आठ गुना आधिक है। व्यक्तिगत बीमारियों के इस तरह के जश्न मनाने वाले खुलासे दूसरों के लिए जागरूकता पैदा कर सकते हैं दृ और संभवतः कई लोगों की जान बचा सकते हैं, खासकर जब

जाने वाले किसी भी तिल के र, आकार और रंग में किसी भी व की लगातार जांच करने के बोत्साहित किया है। बेशक, यह पक्किगत तथ्यों को साझा करने जश्न मनाने वालों की प्रोफाइल लोकप्रियता को नुकसान नहीं देता है क्योंकि इससे उनके प्रति सहानुभूति आकर्षित होती है। लेकिन, हम यह भी सुन रहे थे कि गारा फर्ग्यूसन और प्रिस एंड्रयू के बीच तलाक के बाद बहुत संबंध थे, फिर से एक साथ बचते हैं। जबकि बाद की खबरों में गोई आधार नहीं हो सकता है (भारत में “पूनम पांडे” रस्टंट), तो कम डचेस ने अपनी बीमारी और स्ट्रेमाल कैंसर के बारे में बताकर फैलाने के लिए किया। यह पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। ग्रेटा थुनबर्ग अब न केवल जलवायु परिवर्तन के खिलाफ विरोधी बल्कि वह हर जगह मौजूद हैं जहां वह परेशानी खड़ी कर सकती हैं। वह अपने सही और गलत को समझने में भी काफी होशियार है। ऐसे में हाल ही में उन्हें लंदन के एक पांच सितारा होटल में तेल कंपनियों के सम्मेलन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जब उसे अदालत में पेश किया गया, तो वह बच गई क्योंकि न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस ने न तो यह स्पष्ट निर्देश दिया कि वह होटल में नहीं तो कहां विरोध कर सकती है। न ही उसके लिए कहां विरोध करना कानूनी है। तो, यह पुलिस ही थी जिसने ग्रेटा को नहीं, बल्कि पुलिस को फटकार लगाई। जाहिर तौर पर उन्हें अपना काम करते हुए पुलिस की क्षमताओं में सुधार के लिए उसे एक विशेष पास देना चाहिए। और साथ ही वह जलवायु परिवर्तन को भी खबरों में

ਅਤਰਾਖਣ ਕੀ ਬਡੀ ਏਂ ਸਾਰਥਕ ਪਹਲ

इसका उल्लेख है। इस लिहाज से राजनीति की सभी धाराएं इस बात पर एकमत रही हैं कि देश में सभी पंथों, आस्थाओं से जुड़े लोगों पर एक ही तरह के कानून लागू होने चाहिए। राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति, वर्ग, सम्प्रदाय, जाति जब-तक कानूनी प्रावधानों के भेदभाव को छोलेगा, तब तक राष्ट्रीय एकता, एक राष्ट्र की चेतना जागरण का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता। उत्तराखण्ड एवं गोवा के बाद असम और गुजरात जैसे राज्य भी समान आचार सहिता को लागू करने की तैयारी में हैं। भारतीय जनता पार्टी एवं नरेन्द्र मोदी सरकार यूसीसी लागू करने की मांग जोरदार तरीके से करती आ रही है और इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाया है। भारतीय न्यायपालिका की तरफ से भी बार-बार इसे लागू

ऐसे में यह माना जा सकता है कि देश में इसे लेकर जागरूकता हाल के दिनों में बढ़ी है और इसका श्रेय भाजपा को दिया जाना चाहिए। समान नागरिक संहिता दरअसल एक देश एक कानून की अवधारणा पर आधारित है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत देश के सभी धर्मों, पंथों और समुदायों के लोगों के लिए एक ही कानून की व्यवस्था का प्रस्ताव है। भारत के विधि आयोग ने राजनीतिक रूप से अतिसंवेदनशील इस मुद्दे पर देश के तमाम धार्मिक संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए थे। यूसीसी में संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन, विवाह, उत्तराधिकार, तलाक और गोद लेना आदि को लेकर सभी के लिए एकसमान कानून बनाया जाना है। पिछले कुछ समय से इस पर अच्छी खासी बहस चली अलग—अलग राज्यों में इसे लागू करने और वहाँ के अनुभव के आधार पर आगे बढ़ने का ख्याल गलत नहीं कहा जा सकता। उम्मीद की जानी चाहिए कि उत्तराखण्ड विधानसभा में इसे पेश किए जाने और वहाँ बहस शुरू होने के बाद इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर रोशनी पड़ेगी और सभी दुविधाएं, शकाएं एवं संदेह दूर हो जाएंगे। जो अन्य राज्यों के लिये लागू करने का आधार बनेगी।

भारतीय संविधान के मुताबिक भारत एक धर्म—निरपेक्ष देश है, जिसमें सभी धर्मों व संप्रदायों को मानने वालों को अपने—अपने धर्म से सम्बन्धित कानून बनाने का अधिकार है। भारत में दो प्रकार के पर्सनल लॉ हैं। पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1956 जो कि हिंदू सिख, जैन व अन्य संप्रदायों पर लागू होता है। दूसरा,

लिए लागू होने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ। ऐसे में जबकि मुस्लिमों को छोड़कर अन्य सभी धर्मों व संप्रदायों के लिए भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत बनाया गया हिंदू मैरिज एक्ट 1956 लागू है तो मुस्लिम धर्म के लिए भी समान कानून लागू होने की बात की जा रही है, जो प्रासंगिक होने के साथ नये बन रहे भारत की अपेक्षा है। अभी मीडिया में छन-छन कर जो सूचनाएं आ रही हैं, उनके मुताबिक शादी, तलाक, अड़ॉशन से जुड़े कानूनों में एकरूपता के जो प्रावधान हैं, वे यूसीसी की मूल अवधारणा के अनुरूप ही हैं। बहरहाल, उत्तराखण्ड राज्य सरकार की यह एक बड़ी पहल है और इस पर अमल की प्रक्रिया ही नहीं, इसके नतीजों पर भी पूरे देश की नजरें रहेंगी। आज जबकि भारत विश्वगुरु

की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र के नेतृत्व में भारत कर चुका भारत की अहिंसा एवं योग को न ने स्वीकारा है, विश्व योग एवं विश्व अहिंसा दिवस जैसे जनों की संरचना हुई है। इन नकारात्मक स्थितियों को देखते भारत की कानून विषयक अतियों को दूर करना अपेक्षित योंकि विश्व के कई देशों में नागरिक संहिता का पालन है। इन देशों में पाकिस्तान, आदेश, मलेशिया, तुर्किये, शिया, सूडान, मिस्र, अमेरिका, लैंड, आदि शामिल हैं। इन देशों में सभी धर्मों के लिए मान कानून है और किसी धर्म मुदाय विशेष के लिए अलग न नहीं हैं। लेकिन भारत में अतिक फायदे के लिए तुष्टिकरण

